International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 04, No. 02(II), April - June, 2022, pp. 158-162

राजस्थान में स्कूली शिक्षाः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. राजेश कुमार जांगीड़*
ओमदत्त परेवा**

प्रस्तावना

राजस्थान की भौगोलिक, जनसंख्यात्मक और शैक्षणिक स्थिति का परिदृश्य

भारत के कुल क्षेत्रफल में से राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के साथ देश में प्रथम स्थान है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41 प्रतिशत है। अतः राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी देश के बराबर है।

जनसंख्या के दृष्टिकोण से राजस्थान का भारत में 8वाँ स्थान है। राजस्थान की वर्तमान जनसंख्या 06. 85 करोड़ है जो देश की 05.66 प्रतिशत आबादी के रूप में है। राजस्थान का जनघनत्व देश के मायने में बहुत कम 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान राजस्थान की कुल साक्षरता दर 66.10 प्रतिशत है जिनमें पुरूष साक्षरता 79.20 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 52.10 प्रतिशत है।

राजस्थान की बढ़ती जनसंख्या और साक्षरता के आँकड़ों का वर्गीकरण।

वर्ष	राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर		राजस्थान में साक्षरता वृद्धि दर	
	कुल जनसंख्या (करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	कुल साक्षरता दर (प्रतिशत में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1951	1.59	13.68	8.02	03.10
1961	2.01	26.41	15.21	07.19
1971	2.57	27.86	19.07	03.86
1981	3.42	33.07	23.38	05.31
1991	3.40	28.65	38.55	13.17
2001	5.64	28.18	61.03	22.48
2011	6.85	21.45	66.10	05.07

स्त्रोत : जनसांख्यिकी विभाग, भारत व राजस्थान की जनगणना, दशकीय प्रतिवेदन, 1951 से 2011

विश्लेषण, से स्पष्ट है कि राजस्थान की कुल साक्षरता दर के आधार पर 1951 से 2011 तक 70 वर्षों में साक्षरता की दर 66.10 प्रतिशत तक ही पहुँच पायी है। भारत के साथ साथ राजस्थान में भी पुरूष और महिलाओं की साक्षरता दर में हमेशा ही बहुत असमानताएँ रही है। राजस्थान के इतिहास को जानने पर पता चलता है कि राजस्थान में सामंतवादी परम्परा के परिणामस्वरूप शिक्षा की दर हमेशा से निम्न रही है। राज्य की विषम भौगोलिक संरचना जो राज्य को दो अलग अलग भौगोलिक प्रदेश में विभाजित करती है। सामान्यतः

* सह–आचार्य, राजकीय महाविद्यालय रेलमगरा, राजसमंद, राजस्थान।
** अर्थशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

अरावली पर्वतमाला विभाजक के रूप में पश्चिमी रेगिस्तानी तथा पूर्व मैदानी राजस्थान को विभाजित करने में अहम् भूमिका निभाती है। भौगोलिक विषमता की वजह से ही परिणामतः सम्पूर्ण राज्य में आर्थिक विषमताएँ भी बहुत अधिक है। जिसके प्रभाव ने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा की दर को भी अत्यधिक प्रभावित किया है। हालांकि स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् राजस्थान में निरन्तर विद्यालयी शिक्षा के विकास हेतु राज्य सरकारों, स्वयं सेवी संगठनों और धन्ना सेठों द्वारा प्रयास किए जाते रहे है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लगातार केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाएँ प्रतिपादित की जाती रही है। जिनका संचालन राज्य स्तर पर औपचारिक संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य व सर्वसुलभ उपलब्ध करवाए जाने के भी विभिन्न प्रयास जारी है। लेकिन फिर भी सरकारी आँकड़ों के अनुसार राजस्थान में निरक्षरता की दर अभी भी अधिक है यद्यपि 33.90 प्रतिशत लोग अभी भी साक्षरता की पहुँच से बाहर है।

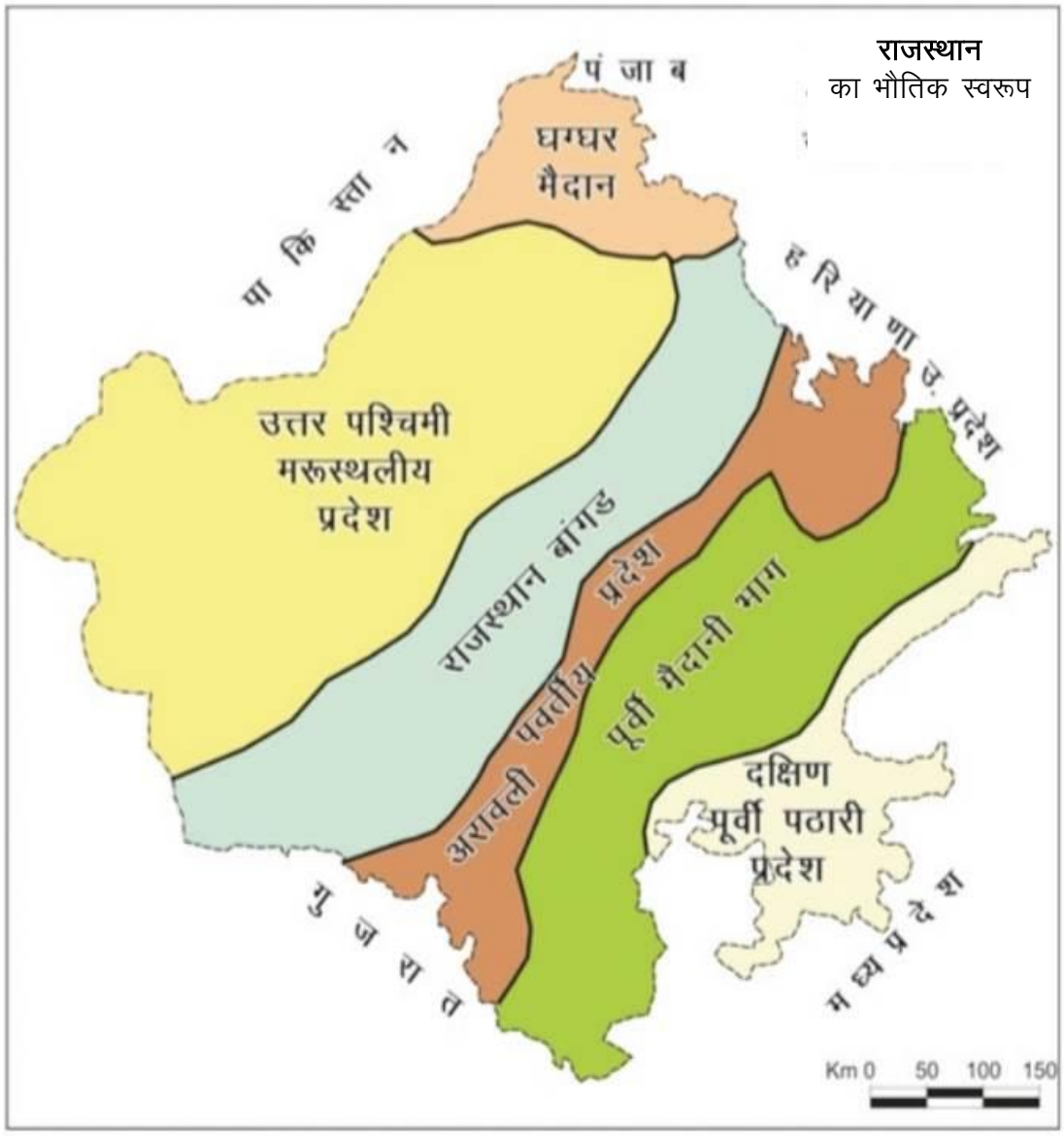

चित्र : राजस्थान का भौतिक स्वरूप

भारत, राजस्थान और जयपुर जिले की साक्षरता दर पुरूष व महिला वर्गों के आधार पर तुलनात्मक वर्गीकरण।

वर्ष	भारत साक्षरता दर (प्रतिशत में)		राजस्थान साक्षरता दर (प्रतिशत में)		जयपुर जिला साक्षरता दर (प्रतिशत में)	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1951	13.88	02.66	27.16	08.86	–	–
1961	28.08	07.01	40.40	15.35	–	–
1971	33.87	10.06	45.96	21.97	–	–
1981	43.77	13.00	56.40	29.80	–	–
1991	53.99	20.44	63.13	39.29	53.80	11.80
2001	75.70	43.85	75.85	43.9	83.50	56.18
2011	79.20	52.10	79.20	52.10	86.10	63.00

स्त्रोत : जनसांख्यिकी विभाग, भारत व राजस्थान की जनगणना, दशकीय प्रतिवेदन, 1951 से 2011

विश्लेषण, तालिका 3.1.4 से स्पष्ट है कि भारत और राजस्थान राज्य में वर्ष 1951 से लेकर वर्तमान जनगणना 2011 तक महिला व पुरूष साक्षरता दरों में काफी असमानता प्रत्येक दशक में प्राप्त हुई है। साथ ही वर्ष 1991 से लेकर 2011 के बीच के आँकड़ों से जाहिर होता है कि राजस्थान और जयपुर जिले की पुरूष व महिला साक्षरता दरों में भी बहुत असमानतापूर्ण विकास हुआ है।

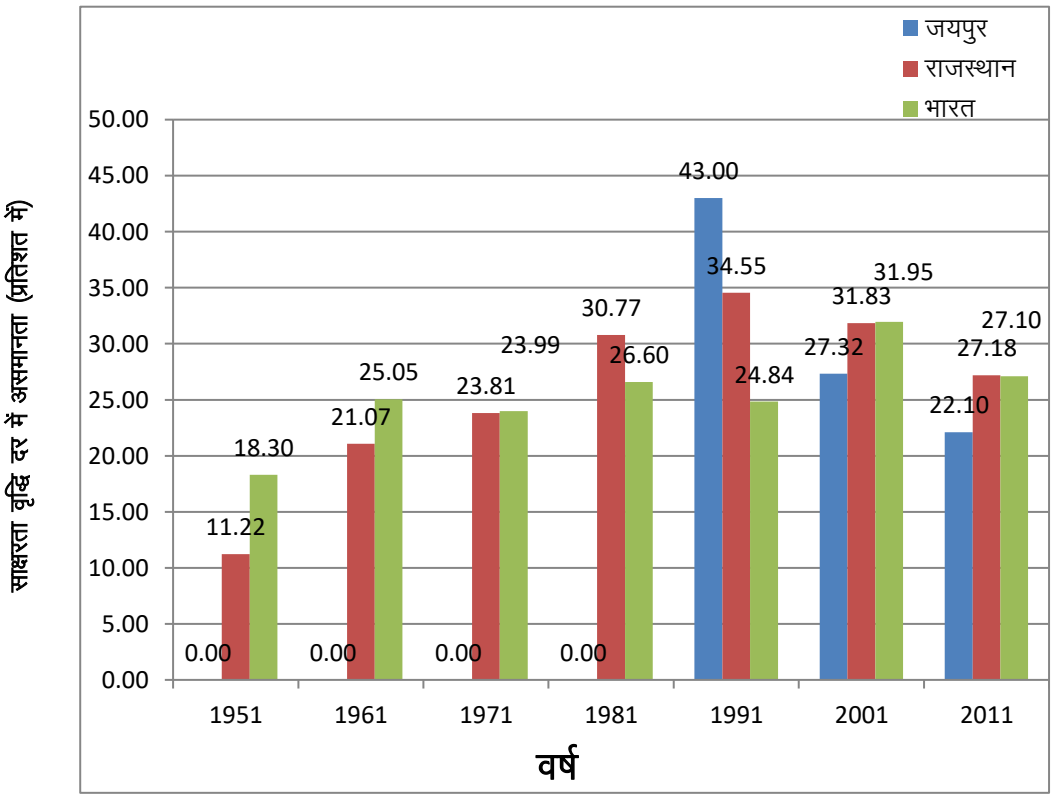

चित्रः भारत, राजस्थान और जयपुर जिले की पुरूष व महिला साक्षरता दर में अन्तरों का बार ग्राफीय निरूपण।

विश्लेषण, उपर्युक्त बार ग्राफ के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1951 से लेकर 2011 तक भारत, राजस्थान, जयपुर जिले की साक्षरता दरों में महिला व पुरूष अन्तराल प्रत्येक दशक में असमान ही रहा है। अतः पुरूषों की साक्षरता दर प्रत्येक दशक में महिलाओं की अपेक्षा अधिक रही है जो शिक्षा के लैंगिक असमान विकास की ओर संकेत करती है।

वर्तमान राजस्थान में सरकारी प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा की स्थिति का विश्लेषण

राजस्थान में प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर, राजस्थान द्वारा सत्र 2019–20 के प्रतिवेदनानुसार 69,929 संपूर्ण (कक्षा 1 से 12 तक) सरकारी विद्यालय है। जिनमें से कुल 85,75,559 विद्यार्थी नामांकित है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में 03.25 लाख अध्यापक अध्यापनरत है। वहीं राज्य में 35,632 विद्यालय (कक्षा 1 से 12 तक) जिनमें कुल 78,69,589 विद्यार्थी नामांकित है। जिनमें कुल 03.32 लाख अध्यापक अध्यापनरत है। अतः यह आँकड़े प्रारम्भिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर के वार्षिक प्रतिवेदन अभिलेख सत्र 2019–2020 के अनुसार लिखित है।[1]

निष्कर्षत

राजस्थान में शाला दर्पण पोर्टल के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, सत्र 2019 से 2020 के अनुसार सभी प्रकार के कुल सरकारी विद्यालयों की संख्या 66,746 है। जिनमें कुल 86,15,770 विद्यार्थी अध्ययनरत है। सत्र 2019 से 2020 में कुल अध्यापकों की संख्या 3,42,462 है। यह आँकड़े इसलिए जानना आवश्यक है कि प्राथमिक शिक्षण स्तर (कक्षा 1 से 8 तक) पर क्या अध्यापक और विद्यालय सहायक संसाधन पर्याप्तता में उपलब्ध है।

राजस्थान में सरकारी विद्यालयों का विभिन्न स्तरों के आधार पर वर्गीकरण।

क्र.सं.	विद्यालय स्तर	कुल विद्यालय संख्या
1.	केवल प्राथमिक विद्यालय	31,561
2.	प्राथमिक के साथ उच्च प्राथमिक विद्यालय	18,918
3.	केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय	217
4.	प्राथमिक, उच्च प्राथमिक के साथ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय	11,239
5.	उच्च प्राथमिक के साथ माध्यमिक विद्यालय	643
6.	उच्च प्राथमिक के साथ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय	348
7.	प्राथमिक व उच्च प्राथमिक के साथ केवल माध्यमिक	3,668
8.	केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक	152

स्त्रोत : राजस्थान, शैक्षणिक आँकड़े, शाला दर्पण पोर्टल, वार्षिक प्रतिवेदन पत्र, 2019 से 2020।

विश्लेषण, तालिका 3.2.1 से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में सरकारी विद्यालयों की स्थिति अलग अलग स्तरों की संख्या भी अलग अलग विभाजित है। अतः इन तथ्यों के आधार पर आगे चलकर सरकारी एवं निजी विद्यालयों की संख्यात्मक तुलना आसानी से की जा सकती है।

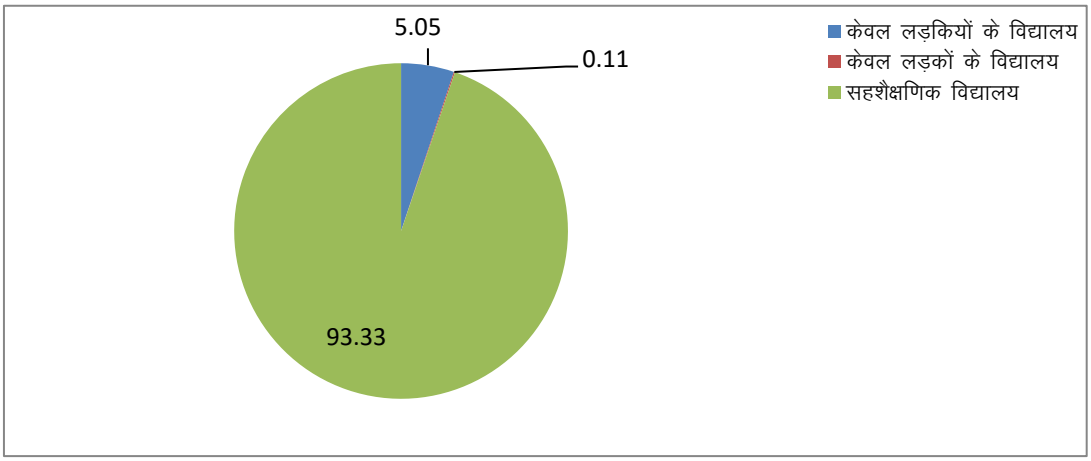

चित्रः वर्तमान राजस्थान में लड़कियों, लड़कों और सहशैक्षणिक सरकारी विद्यालयों की स्थिति का वृत्तीय निरूपण

[1] वार्षिक प्रतिवेदन अभिलेख, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर, राजस्थान, 2019–2020।

विश्लेषण, उपर्युक्त चित्र से स्पष्ट है कि 66,764 सरकारी विद्यालयों में से 93.33 प्रतिशत सहशैक्षणिक विद्यालय, 05.05 प्रतिशत केवल लड़कियों के विद्यालय तथा 0.11 प्रतिशत केवल लड़कों के विद्यालय वर्तमान में स्थापित है।

वर्तमान राजस्थान में सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों की संख्यात्मक स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण

सरकारी विद्यालयी व्यवस्था, सरकारी विद्यालयी व्यवस्था वह होती है जिसे राज्य या सरकार द्वारा बिना किसी व्यक्तिगत शुल्क के वित्तपोषित अथवा सरकारी नियंत्रण स्वरूप संचालित व प्रशासित किया जाता है। सभी सरकारी विद्यालयों में राष्ट्रीय स्तर की सरकारी शिक्षण संस्था द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को ही राष्ट्रीय स्तर पर सभी सरकारी विद्यालयों द्वारा एक समान रूप से लागू किया जाता है। अध्यापकों की नियुक्ति भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सहित उच्च सुयोग्य अभ्यर्थियों को शिक्षण कार्य हेतु लिखित परीक्षा मैरिट आधारित प्रक्रिया द्वारा भर्ती किया जाता है। जिनकी तनख्वाह राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर तय स्केल के आधार पर अपनी निधियों से प्रदान की जाती है।

निजी विद्यालयी व्यवस्था, निजी विद्यालयी व्यवस्था वह होती है जिसे राज्य द्वारा वित्त पोषित, संचालित तथा प्रशासित नहीं किया जाता है। जबकि निजी विद्यालयों को स्थापित करने या मान्यता प्रदान करने का कार्य सरकारी संस्था के नियमानुसार राज्य या सरकार का ही होता है। अतः आंशिक रूप से या बहुत कम नियंत्रण तथा निगरानी राज्य या सरकार की रहती है। यद्यपि निजी विद्यालय एक निजी निकाय या व्यक्तिगत नियंत्रण द्वारा प्रशासित होता है। निजी विद्यालयों में फीस विद्याथियों के ट्यूशन कक्षाओं के आधार पर व्यक्तिगत या निजी निकाय द्वारा स्व तय की जाती है। निजी विद्यालयों में भी राज्य द्वारा या अशासकीय विद्यालय बोर्डों द्वारा तय पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाता है अतः इनका कोई निजी पाठ्यक्रम होता है। निजी विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया सरकारी विद्यालयों में होने वाली लिखित परीक्षा मैरिट भर्ती प्रक्रिया की बजाय सीधी भर्ती या मौखिक साक्षात्कार के आधार पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देखकर एक लचीली प्रक्रिया द्वारा अध्यापकों को शिक्षण कार्य हेतु भर्ती किया जाता है। इन अध्यापकों की तनख्वाह निजी निकाय या व्यक्तिगत संचालकों द्वारा तय की जाती है तथा विद्यार्थियों से प्राप्त ट्यूशन फीस या निजी स्त्रोतों से प्रदान की जाती है। अतः जैसे जैसे शिक्षा का निजीकरण होता गया वैसे वैसे वस्तुतः राज्य एवं सरकार का इन निजी विद्यालयों पर नियंत्रण तथा निगरानी भी बहुत न्यून होती चली गई।

अतः राजस्थान में सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों का तुलनात्मक विस्तार देखा जाए तो पाते है कि सम्पूर्ण विद्यालयों की संख्या 1,05,674 है। जिनमें 1,74,95,599 विद्यार्थी अध्ययनरत है तथा 7,15,620 अध्यापक अध्यापनरत है। सम्पूर्ण राजस्थान में विद्यालयी शिक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु 302 खण्डों में विभाजित किया हुआ है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. वार्षिक प्रतिवेदन अभिलेख, प्रारंभिक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर, राजस्थान, 2019–2020।
2. गैर सरकारी संगठन, प्रथम, असर, वार्षिक प्रतिवेदन पत्र, 2017।
3. राजोरा, डॉ. सुरेशचन्द, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं चुनौतियाँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, पाठ्यपुस्तक मण्डल प्रकाशन, जयपुर, 2016, पृष्ठ संख्या 21।

❖◆❖